



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 22—अगस्त 28, 2015 (श्रावण 31, 1937)

No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 22—AUGUST 28, 2015 (SRAVANA 31, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....

819

छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....*

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....

789

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियाँ भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....*

1

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....*

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....

2157

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....

1107

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....*

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंट्स और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....*

381

भाग II—खण्ड-1—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....*

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....*

757

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रबंध समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....*

भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियाँ आदि भी शामिल हैं).....*

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के अंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.*

*अंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

Page No.		Page No.	
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	819	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	789	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2157	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1107
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	381
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	757
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की
गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

**[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली—110011, दिनांक 5 अगस्त 2015

संकल्प

सं. 1/09/2014—हिन्दी—उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के दिनांक 23 अगस्त, 2012 के संकल्प संख्या 1/02/2010—हिन्दी का अधिकमण करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन करती है :—

संरचना

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री

डॉ. जितेन्द्र सिंह

अध्यक्ष

गैर—सरकारी सदस्य :—

लोक सभा से दो संसद सदस्य

1. श्री रामेश्वर तेली

सदस्य

2. श्री विष्णु पद राय

सदस्य

राज्य सभा से दो संसद सदस्य

3. श्री भुवनेश्वर कालिता

सदस्य

4. श्री विश्वजीत डायमरी

सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति से दो संसद सदस्य

5. श्री श्रीराम आप्पा बारणे

सदस्य

6. श्री सत्यग्रत चतुर्वेदी

सदस्य

केंद्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, एक्सवार्इ—68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली से प्रतिनिधि

7. श्री आर. के. दिविवेदी

सदस्य

बी—101, एम. एस. अपार्टमेंट

के. जी. मार्ग, नई दिल्ली—110001

अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, 10788—89, झंडेवालान रोड, नवी करीम, नई दिल्ली—110055 से प्रतिनिधि

8. डॉ. क्षीरदा कुमार शाइकीया

सदस्य

मंत्री, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति,

राष्ट्रभाषा प्रकल्प, सेवा मंदिर पथ,

रूपनगर, गुवाहाटी—781032 (असम)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा नामित गैर—सरकारी सदस्य

9. डॉ. बलवंत शास्त्री

सदस्य

401 वसुधरा एन्कलेव,

बंगाली कंपाउन्ड, गोकुलधाम,

गोरगांव पूर्व, मुंबई (महाराष्ट्र),

दूरभाष : 022—40214917

10.	श्री कृलेश्वर सोनकर 102, कल्पतरु लेक व्यू अपार्टमेंट, जे. पी. नगर, 7वां फेज़, बैंगलूरु—560078 दूरभाष : 080—42351113	सदस्य
11.	शास्त्री विपन खजूरिया, मकान नं. 461, जुलाका मोहल्ला जम्मू—180001 मो. : 09419124127	सदस्य
12.	डॉ. राजेन्द्र सिंह चंदेल विनिता विहार, स्कीम सं. 103, प्लाट सं. 507—508, चोइथराम मण्डी इन्डौर, मंत्रा मोटर्स इन्डौर के पीछे (म. प्र.) फोन : 09827321584	सदस्य
	गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा नामित गैर—सरकारी सदस्य	
13.	सुश्री सुजय डे मकान सं. 102 /ए, त्रिवेणी हाउसिंग कॉम्प्लैक्स अदाबाड़ी तिनियाली पांडु, गुवाहाटी—781012 मो. 09716984621	सदस्य
14.	डॉ. दिग्विजय सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर लेन नं. 3, गौतम नगर, सुसुवाही, वाराणसी—221005 मो. 09415369918	सदस्य
15.	डॉ. लक्ष्मी नारायण मित्तल मकान नं. एच—902, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मुरैना—476001, मध्य प्रदेश मो. 08989479298	सदस्य

सरकारी सदस्य :—

	राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)	
16.	सचिव	सदस्य
17.	संयुक्त सचिव	सदस्य
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	
18.	सचिव	सदस्य
19.	संयुक्त सचिव (वीबीपी)	सदस्य
20.	संयुक्त सचिव (जेकेएस)	सदस्य
21.	संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार	सदस्य
22.	वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार	सदस्य
23.	सभी निदेशक /उप सचिव, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	सदस्य
24.	सचिव, पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग	सदस्य
25.	प्रबंध निदेशक, एन ई एच एच डी सी, गुवाहाटी	सदस्य
26.	प्रबंध निदेशक, नेरामेक, गुवाहाटी	सदस्य
27.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेडफी, गुवाहाटी	सदस्य
28.	संयुक्त सचिव, (राजभाषा प्रभारी)	सदस्य—सचिव

II. कार्य

समिति का कार्य केंद्रीय हिंदी समिति और राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी कामकाज के लिए हिंदी के प्रयोग के संबंध में निर्धारित नीतियों को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में कार्यान्वित करवाने के बारे में सलाह देना होगा।

III. कार्यकाल

समिति का कार्यकाल समिति की गठन की तारीख से निम्नलिखित बातों के अधीन सामान्यतः तीन वर्ष का होगा :

- (क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने की स्थिति में इस समिति के सदस्य नहीं होंगे।
- (ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर बने रहने तक ही समिति के सदस्य रहेंगे।
- (ग) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण खाली हुए स्थान को मनोनीत सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होंगे।

IV. मुख्यालय

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा किंतु समिति अपनी बैठकें आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

V. यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/20034/04/2005—रा.भा. (नीति-2) दिनांक 03 फरवरी, 2006 द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित हिंदी सलाहकार समितियों में नामित 15 गैर—सरकारी सदस्यों में 06 संसद सदस्य होते हैं, अतः यात्रा/दैनिक भत्ता प्रावधान को अधिक स्पष्ट करते हुए निम्न प्रावधान किया जाता है :—

- (क) समिति में नामित सांसदों को “संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेशन) अधिनियम, 1954” के प्रावधानों एवं समय—समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जायेगा।
- (ख) समिति ने अन्य गैर—सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/22034/04/86—रा.भा. (क-2) में निहित दिशा निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय—समय पर संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक—एक प्रति उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सभी सदस्यों राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों और सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, भुगतान और लेखा कार्यालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत निकायों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ए. एम. सिंह,
संयुक्त सचिव

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2015

संकल्प

सं. 1—36/2014—एसडीई—देश में सभी प्रकार के कौशलीकरण और उद्यमशीलता के लिए एक वृहत् और संपूर्ण रोडमैप निर्धारित करने के लिए मंत्रिमंडल ने 01 जुलाई, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में मंत्रिमंडल सचिवालय की सूचना संख्या—27/सीएम/2015(आई) दिनांक 02 जुलाई, 2015 के द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति 2015 को अनुमोदित कर दिया है।

इस नीति का विजन “उच्च मानकों और गति के साथ बड़े पैमाने पर कौशलीकरण के द्वारा सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और नवीनता आधारित उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना है, जिससे धन और रोजगार पैदा हो सके, ताकि देश में सभी नागरिकों के लिए सतत आजीविका सुनिश्चित हो सके”।

इस नीति में कौशलीकरण और उद्यमशीलता परिदृश्य, जिस क्षेत्र की तरफ कम आकांक्षा, औपचारिक शिक्षा के साथ गैर-एकीकरण, परिणाम पर ध्यान केंद्रित न होना, प्रशिक्षण अवसंरचना और प्रशिक्षकों की गुणवत्ता, आदि शामिल हैं, में मुख्य बाधाओं के समाधान का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, इस नीति का उद्देश्य आपूर्ति को मांग के अनुरूप करना, वर्तमान कौशल—अंतराल को भरना, उद्योग व्यवस्था को बढ़ावा देना, गुणवत्ता—आश्वासन—ढांचा प्रचालनरत करना, प्रौद्योगिकी का फायदा उठाना और कौशल के क्षेत्र में आने वाले मुद्दों से निपटने के लिए शिक्षुता को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य सामाजिक/भौगोलिक रूप से हाशिए पर आए लोगों और वंचित समूहों तथा महिलाओं के लिए कौशल शिक्षण का समान अवसर प्रदान करने को बढ़ावा देना भी है। उद्यमशीलता के क्षेत्र में इस नीति में औपचारिक/कौशल शिक्षा के अंग के रूप में समर्थन और उद्यमशीलता शिक्षा के एकीकरण के जरिए उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देना, क्रेडिट और बाजार संपर्क की दृष्टि से उद्यमियों के लिए सहायता में वृद्धि करना, नवीनता आधारित सामाजिक उद्यमों का संपोषण करना और व्यापार करने में सरलता लाना है। इसमें सामाजिक/भौगोलिक रूप से हाशिए पर आए लोगों और वंचित समूहों की उद्यमशीलता आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयासों के अतिरिक्त महिलाओं में उद्यमशीलता को आगे और प्रोत्साहित करने के लिए तरीकों के बारे में सुझाव भी दिया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

राजेश अग्रवाल
संयुक्त सचिव

संकल्प

सं. बी—12013/23/2015—एसडीई—देश भर में कौशल विकास प्रयासों का एकीकरण करने हेतु समग्र संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए और सभी सेक्टरों में प्रक्रियाओं और परिणामों के मानकीकरण के लिए मंत्रिमंडल ने 01 जुलाई, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में मंत्रिमंडल सचिवालय के सूचना सं.—27/सीएम/2015 (आई) दिनांक 02 जुलाई, 2015 के द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को अनुमोदित कर दिया है।

इस मिशन का ढांचा थी—टायर का होगा। सबसे ऊपर माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शासी परिषद होगा, जो मिशन को समग्र रूप से दिशा—निर्देश और नीति—निर्देश प्रदान करेगा। कौशल विकास के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में संचालन समिति, शासी परिषद द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुरूप मिशन की गतिविधियों की समीक्षा करेगी। कौशल विकास के सचिव, मिशन निदेशालय के निदेशक के रूप में कार्य करेंगे और वह केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों की कौशलीकरण गतिविधियों का कार्यान्वयन, समन्वय और अभिसरण (कन्वर्जन्स) सुनिश्चित करेंगे। यह मिशन उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में चुनिंदा उप-मिशन भी चलाएगा जिसमें से सात उप-मिशनों—अर्थात् संस्थागत प्रशिक्षण, अवसंरचना, अभिसरण (कन्वर्जन्स), प्रशिक्षक, विदेश—रोजगार, सतत आजीविका और लाभग्राही सार्वजनिक अवसंरचना की पहचान प्रारंभिक तौर पर कर ली गई है। इसके अलावा, एनएसडीए, एनएसडीसी और प्रशिक्षण निदेशालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के प्रशासनिक ढांचे के तहत कार्य करते हुए मिशन निदेशालय के कार्यपालिक अंग के रूप में कार्य करेंगे। एमएसडीई, मिशन का आलंब होगा जो सभी तीन निर्णायक स्तरों को स्वाभाविक रूप से जोड़ेगा और सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ—राज्य क्षेत्र की सरकारों के कौशलीकरण पारिस्थितिकी तंत्र का अभिसरण (कन्वर्जन्स) सुनिश्चित करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

राजेश अग्रवाल
संयुक्त सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली—110003, दिनांक 29 जुलाई 2015

डिजिटल पहचान के रूप में मोबाइल पर दिशा—निर्देश

सं. 3(54) / 2014—ईजी-II—जबकि, डिजिटल इंडिया के महत्वाकांक्षी विजन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) भारत सरकार (जीओआई) का उद्देश्य सभी सरकारी सेवाएं वेब, मोबाइल और सामान्य सेवा प्रदायगी आउटलेट

जैसे बहु-चैनलों के जरिए नागरिकों के लिए डिजिटल रूप में अभिगम योग्य बनाना है। भारत को डिजिटल रूप से एक सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश में इतने बड़े मोबाइल फोन उपभोक्ता आधार का लाभ उठाना अनिवार्य है। अतः भारत सरकार ने मोबाइल उपकरणों के जरिये भी सार्वजनिक सेवाओं के अभिगम का प्रावधान करने का निश्चय किया है।

और जबकि, सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी के लिए डिजिटल पहचान के उपकरणों के रूप में मोबाइल फोन के इस्तेमाल के अपार अवसर हैं। डिजिटल पहचान के लिए अधिप्रमाणन के उपकरणों (साधन) के रूप में मोबाइल फोन के लिए आवश्यक है कि वे अद्वितीय, अधिप्रमाणन योग्य हों और स्वीकार की जाने वाली आवश्यकताओं को पूरा करते हों। इसे प्राप्त करने के संभावित तरीकों में प्रयोक्ताओं के मोबाइल नम्बरों को उनके आधार से लिंक करना शामिल होगा क्योंकि यह एक अद्वितीय और सत्यापन योग्य पहचान है, जिसे विश्वसनीय प्राधिकरण अर्थात् यूआईडीएआई द्वारा जारी किया जाता है।

और जबकि, आधार और मोबाइल के लिंकेज और अधिप्रमाणित डिजिटल पहचान का इस्तेमाल करते हुए देश में शहरी और ग्रामीण जनता दोनों को सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित कदमों (चरणों) की पहचान हेतु सु—निर्धारित ‘डिजिटल पहचान के रूप में मोबाइल पर दिशा—निर्देश’ आवश्यक है।

और जबकि, सक्षम प्राधिकारी ने डिजिटल पहचान के रूप में मोबाइल पर दिशा—निर्देश अनुमोदित कर दिए हैं।

अब यह विभाग अधिसूचना की तारीख से <http://egovstandards.gov.in> पर प्रकाशित डिजिटल पहचान के रूप में मोबाइल पर दिशा—निर्देशों के इस्तेमाल को एतद्वारा अधिसूचित करता है।

कृष्णा बिदानी
उप निदेशक

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi-110011, the 5th August 2015

RESOLUTION

No. 1/09/2014-Hindi—In supersession of the Ministry of Development of North Eastern Region's resolution No. No. 1/02/2010-Hindi dated 23rd August, 2012, the Government of India hereby, reconstitutes the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Development of North Eastern Region as under :—

COMPOSITION

Minister of Development of North Eastern Region

Dr. Jitendra Singh Chairman

Non Official Members :—

Two MPs from Lok Sabha

- | | | |
|----|---------------------|--------|
| 1. | Sh. Rameswar Teli | Member |
| 2. | Sh. Bishnu Pada Ray | Member |

Two MPs from Rajya Sabha

- | | | |
|----|------------------------|--------|
| 3. | Sh. Bhubaneswar Kalita | Member |
| 4. | Sh. Biswajit Daimary | Member |

Two MPs from the committee of Parliament on Official Language

- | | | |
|----|--------------------------|--------|
| 5. | Sh. Shirang Aappa Barne | Member |
| 6. | Sh. Satyavrat Chaturvedi | Member |

Representative from Kendriya Sachivalaya Hindi Parisad, XY-68 Sarojini Nagar, New Delhi

- | | | |
|----|--|--------|
| 7. | Shri R. K. Dwivedi
B-101, M.S. Apartment
K. G. Marg, New Delhi-110001. | Member |
|----|--|--------|

Representative from Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh, 10788-89, Jhandewalan Road, Nabi Karim, New Delhi-110055

- | | | |
|----|--|--------|
| 8. | Dr. Khirda Kumar Saikia,
Mantri, Asam Rashtrabhasha Prachar Samiti,
Rashtrabhasha Prakalp, Sewa Mandir Path,
Roop Nagar, Guwahati-781032 (Assam). | Member |
|----|--|--------|

Non-Official Members nominated by the Ministry of Development of North-Eastern Region

- | | | |
|-----|---|--------|
| 9. | Dr. Balwant Shastri,
401, Vasundhara Enclave,
Bangali Compound, Gokuldham,
Goregaon East, Mumbai (Maharashtra),
Tel. : 022-40214917 | Member |
| 10. | Shri Kuleshwar Sonkar,
102, Kalpatharu Lake View Apartments,
J. P. Nagar, 7th Phase,
Bangalore-560078
Tel. : 080-42351113 | Member |
| 11. | Shasti Vipan Khajuria,
H. No. 461, Jullaka Mohalla,
Jammu-180001
Mob. : 09419124127 | Member |

12. Dr. Rajendra Singh Chandel,
Vinita Vihar, Scheme No. 103,
Plot No. 507-508, Near Choithram Mandi Indore,
Behind Mantra Motors Indore (M.P.).
Mob. : 09827321584. Member

Non-official member nominated by the Ministry of Home Affairs
(Department of Official Language)

13. Ms. Sujaya Dey
102/A, Triveni Housing Complex
Adabari Tiniali, Pandu, Guwahati
Pin-Code-781012
Mob. : 09716984621. Member

14. Dr. Digvijaya Singh
Associate Professor, Lane No. 3
Gautam Nagar, Susuvahi
Varanasi-221005
Mob. : 09415369918. Member

15. Dr. Laxmi Narayan Mittal
H. No. H-902, Old Housing Board Colony
Muraina-476001 (M.P.)
Mob. : 08989479298 Member

Official Members

Department of Official Language

16. Secretary	Member
17. Joint Secretary	Member

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

18. Secretary	Member
19. Joint Secretary (VBP)	Member
20. Joint Secretary (JKS)	Member
21. Joint Secretary and Financial Advisor	Member
22. Sr. Economic Advisor	Member
23. All Directors/Deputy Secretaries of M/o DONER	Member
24. Secretary, NEC, Shillong	
25. Managing Director, NEHHDC, Guwahati	Member
26. Managing Director, NERAMAC, Guwahati	Member
27. Chairman & Managing Director, NEDFi, Guwahati	Member
28. Joint Secretary (In-charge O.L.)	Member-Secretary

II. Functions

The functions of the Samiti will be to render advice for the implementation of the policies laid down by Kendriya Hindi Samiti and Department of Official Language regarding the use of Hindi for official purpose in the Ministry of Development of North Eastern Region.

III. Tenure

The tenure of the Samiti will ordinarily be three years from the date of its constitution provided that :—

- (a) the Members of the Parliament who are the members of the Samiti shall cease to be the members of the Samiti as soon as they cease to be the Members of the Parliament;
- (b) ex-officio members of the Samiti shall continue to be the members of the Samiti as long as they hold the office by virtue of which they are the members of the Samiti; and
- (c) if any vacancy arises in the Samiti owing to the death of a member or owing to tendering of resignation by a member, the member so appointed against that vacancy shall hold office for the residual term of the Samiti.

IV. Headquarter

The Headquarters of the Samiti will be at New Delhi, but if considered necessary, it may hold its meetings at any other place also.

V. Travelling and other allowances

The Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, vide their Office Memorandum No. II/20034/04/2005-OL (Policy-2) dated 3rd February, 2006 has stated that as the 15 non-official members include 6 members of Parliament nominated in the Hindi Salahakar Samitis constituted by Central Ministries/Department, so the provision regarding travelling/daily allowance is made more elaborate in the following manner :—

- (a) The members of Parliament nominated in the Samiti will be paid travelling and daily allowance as per the provisions in the “Members of Parliament (Salary, Allowance and Pension) Act, 1954”, amendments issued from time to time and rules made thereunder.
- (b) Travelling Allowance and Daily Allowance to other non-official Members of the Samiti will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language OM. No. II/20034/04/86-OL(A-2) dated 22nd January 1987 and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

ORDER

It is Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of the Development of North Eastern Region, President's Secretariat, Prime-Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, all Ministries/Departments of Government of India, all state governments and union territory administrations, Committee of Parliament on Official Language, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Election Commission, Union Public Service Commission, Pay and Accounts Office, Ministry of DoNER and all Subordinate Offices/Authonomous Bodies of the Ministry of DoNER.

It is also Ordered that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. M. SINGH
Joint Secy.

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

New Delhi, the 15th July 2015

RESOLUTION

No. 1-36/2014-SDE—To lay down a comprehensive and holistic road map for all the skilling and entrepreneurship activities across the Country, the Cabinet in its meeting held on 1st July, 2015 has approved the National Policy for Skill Development and Entrepreneurship, 2015 vide Cabinet Secretariat's Communication No. - 27/CM/2015(i) Dt. 2nd July, 2015.

The Vision of the Policy is “To create an ecosystem of empowerment by Skilling on a large Scale at Speed with high Standards and to promote a culture of innovation based entrepreneurship which can generate wealth and employment so as to ensure Sustainable livelihoods for all citizens in the country”.

The Policy addresses the key obstacles in the skilling and entrepreneurship landscape, including low aspirational value, non integration with formal education, lack of focus on outcomes, quality of training infrastructure and trainers, etc.

Further, the Policy aims to align supply with demand, bridge existing skill gaps, promote industry engagement, operationalise a quality assurance framework, leverage technology and promote apprenticeship to tackle the issues in the skill space. It also aims to promote equitable skilling opportunities for socially/geographically marginalised and disadvantaged groups as well as women. In the entrepreneurship domain, the Policy seeks to promote entrepreneurial culture through advocacy and integration of entrepreneurship education as part of formal/skill education, enhance support for entrepreneurs in terms of credit and market linkages, foster innovation driven social enterprises and improve ease of doing business. It also suggests ways to further fillip entrepreneurship among women besides endeavoring to meet the entrepreneurial needs of socially/geographically marginalised and disadvantaged groups.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all the Central Ministries/Departments and State Governments.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

RAJESH AGRAWAL
Joint Secretary

RESOLUTION

No. B-12013/23/2015-SDE—To provide the overall institutional framework for consolidation of skill development efforts across the Country and standardization of procedures and outcomes across all sectors, the Cabinet in its meeting held on 1st July, 2015 has approved the National Skill Development Mission vide Cabinet Secretariat's Communication No. - 27/CM/2015(i) Dt. 2nd July, 2015.

The Mission will have a three-tiered structure. At its apex, the Mission's Governing Council, chaired by Hon'ble Prime Minister, will provide overall guidance and policy direction to the Mission. The Steering Committee, chaired by Minister-in-Charge of Skill Development, will review the Mission's activities in line with the direction set by the Governing Council. The Mission Directorate, with Secretary, Skill Development as Mission Director, will ensure implementation, coordination and convergence of skilling activities across Central Ministries/Departments and State Governments. The Mission will also run select sub-missions in high priority areas, of which seven have been identified initially viz. Institutional Training, Infrastructure, Convergence, Trainers, Overseas Employment, Sustainable Livelihoods, and Leveraging Public Infrastructure. Further, NSDA, NSDC and Directorate of Training will function under the umbrella framework of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) and act as the executive arms of the Mission Directorate. MSDE shall be the fulcrum of the Mission, organically linking all three decision making levels and ensuring convergence of skilling ecosystem with all the Central Ministries/Departments as well as with State Governments/Government of Union Territories.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all the Central Ministries/Departments and State Governments.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

RAJESH AGRAWAL
Joint Secretary

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi–110003, the 29th July 2015

Guidelines on Mobile as Digital Identity

No. 3(54)/2014-EG-II.—WHEREAS, Department of Electronics & Information Technology (DeitY), under the overarching vision of Digital India, Government of India (GoI) aims to make all Government services digitally accessible to citizens through multiple channels, such as web, mobile and common service delivery outlets. To meet this objective of

transforming India into a digitally empowered society and knowledge economy; it is essential to take advantage of the vast mobile phone subscriber base in the country. GoI has thus decided to also provision for access of public services through mobile devices.

AND WHEREAS, there is tremendous opportunity to use mobile phones as instruments of digital identity for delivery of public services. For mobiles to be instruments of authentication for digital identity, they should be unique, authenticable and fulfill requirements of non-repudiation. A possible way of achieving the same would be to link the mobile numbers of users to their Aadhaar, a unique and verifiable identity provided by a trusted authority, UIDAI.

AND WHEREAS, a well laid “Guideline on Mobile as Digital Identity” is essential for identifying the proposed steps to build the linkage of Aadhaar & Mobile and ensure delivery of public services both in urban and rural populace in the country using authenticated digital identity.

AND WHEREAS, the Competent Authority has approved the Guideline on Mobile as Digital Identity.

NOW, this Department hereby notifies the use of Guideline on Mobile as Digital Identity published on <http://egovstandards.gov.in> w.e.f. the date of notification.

KRISHANA BIDANI
Deputy Director